

संपादकीय

एक विचार प्रज्वलित

जम्मू-कश्मीर में एक भूत का साया मड़ा रहा है। हमारे सबसे संकटग्रस्त भूगोल के लिए यह कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन यह हिंसक मौत का भूत नहीं है जो फिर से अपनी रफतार पकड़ रहा है और खून से लथपथ पैरों के साथ नई जमीन पर चल रहा है। यह अद्वितीय रशीद शेख का भूत है, जिसे इंजीनियर रशीद के नाम से बेहतर जाना जाता है, जो बारामुल्ला से लोकसभा के स्वतंत्र सदस्य हैं। इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि रशीद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत तिहाड़ जेल में हैं, या यह कि उनके जल्द ही बाहर आने की संभावना अवास्तविक है। इंजीनियर रशीद एक ज्वलंत विचार बन गए हैं, राज्य के साधनों के माध्यम से विद्रोह का विचार। उस विचार को कैद या रोका नहीं जा सकता। यह रशीद द्वारा बारामुल्ला लोकसभा सीट हथियाने के तथ्य के बारे में नहीं है यह इसके फैशन के बारे में है। संसद पहुँचने के रास्ते में वह किसे हराते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अद्वितीय को और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी – में इस बात को लेकर कंपकंपी है कि राशिद की जीत और उसके व्यापक तरीके का क्या मतलब हो सकता है, हालांकि वे अभी इसे स्वीकार करने से कतराएँगे। राशिद एक ऐसी भावना और एक ऐसे मतदाता वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बारे में बहुत कम भ्रम हो सकता है – यह गहराई से और बुनियादी तौर पर राज्य विरोधी है। सिर्फ बारामुल्ला में ही नहीं बल्कि घाटी भर में मतदाताओं की बढ़ती संख्या ने अगस्त 2019 में लगाए गए प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि इस उपाय और उसके बाद जो हुआ उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। राशिद या उनके जैसे वैचारिक रूप से अलग-थलग लोगों को मतदाता जनता की नाराजगी और आक्रोश का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देख सकते हैं। राशिद के बेतहाशा अभियान का मुख्य नारा – जेल का बदला वोट से लेंगे। – शायद जमीन पर मौजूद प्रमुख मूड को पकड़ने के सबसे करीब है। मैं इंजीनियर राशिद से पहली बार 2008 में मिला था। उन्होंने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ विद्रोह किया था – उस समय भी अलगाववादी झंडा फहरा रहे थे – और बारामुल्ला में अपने पैतृक क्षेत्र लंगेट से निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वह तब, जैसा कि वह कई मायनों में आज भी है, एक अजीबोगरीब व्यक्ति था जो एक विशेष रूप से नियत भूमिका के प्रति आश्वस्त था। उसके पास कोई पार्टी या अनुयायी नहीं थे। उसके पास अपने खुद के कोई संसाधन नहीं थे। वह एक जर्जर झोंपड़ी में रहता था, जिसके फर्श पर घास बिखरी हुई थी और जिसकी मिट्टी की दीवार एक गौशाला से मिलती थी। वह जूते न पहनने का वादा करता था और उसके मुंह से गोवंश की बदबू आती थी। वास्तव में वह एक अस्वच्छ व्यक्ति था जो आश्वस्त था कि वह एक घटना बनने की राह पर है। वह एक ऐसे व्यक्ति की भावना को प्रकट करता था जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, विशेष रूप से उसके अलंकृत और अक्सर बहुत स्पष्ट और उत्तेजक बोलने के तरीके से। उदाहरण – हम राज्य द्वारा हमें जिस भी स्थिति में लाना हो, हम उसी स्थिति में आने के आदी हो गए हैं, हमने खुद को कमतर आंकने की शर्म खो दी है, हम ऐसे ही हैं। वह खुद को एक कथाकार मानता था, कहानियाँ सुनाना पसंद करता था, जिनमें से कई उसने उर्दू अख्घारों में प्रकाशित की थीं एक समय था जब वे ऐसी चीजें प्रकाशित करते थे, जो अब आपको स्थानीय थाने से फोन करके मिल जाती थीं। कई सर्दियाँ ऐसी भी थीं जब हम सोने नहीं जाते थे, वे हमें ऐसा आदमी नहीं मानते थे जिसे वे सक्षम समझते थे। हमें सुबह तीन बजे, कभी-कभी उससे भी पहले बाहर जाने का आदेश दिया जाता था, और सड़क के किनारे जमा बर्फ पर लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। हमें जूते पहनने की अनुमति नहीं थी और केवल न्यूनतम कपड़े पहनने की अनुमति थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई हथियार छिपाए। वहाँ बहुत ठंड होती थी, बर्फ जमी होती थी और सख्त होती थी। ठंड थी लेकिन ऐडियों पर जलते हुए कोयले की तरह महसूस होता था। हम में से हर एक को अपने चेहरे पर लालटेन ऊपर उठा कर रखना था ताकि हमें पहचाना जा सके और फिर हमें अपने आकाओं को आश्वस्त करने के लिए बंदरों की तरह बर्फ पर ऊपर–नीचे कूदना था कि हम कोई हथियार नहीं ले जा रहे हैं, बर्फ में ऊपर–नीचे, ऊपर–नीचे तब तक जब तक कि हम अपने पैरों को महसूस न कर सकें। सुबह की शुरुआत यहीं से होती थी। वे इसे काफिले की डचूटी कहते थे। हम सड़क के दोनों ओर मीलों तक एक-एक कतार में चलते थे, बारादी सुरंगों या विस्फोटकों से बचने के लिए मानव ढाल की तरह। चाहे जो भी हो, हम सैन्य काफिलों के गुजरने के लिए सड़क को सुरक्षित करने के लिए बर्फ को घसीटते थे। जब तक आदेश न दिया जाए, कोई नहीं रुकता, यहाँ तक छक्कि सुन्न होने से बचने के लिए अपने पैरों को रगड़ने या प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए भी नहीं। अगर आप रुकते, तो आपको राइफल के बट से मारा जाता। और आपको गिरना नहीं चाहिए था। अगर आप गिरते, तो आपको जूतों से पेट में लात मारी जाती।

विनिर्माण में सहायता हेतु इंजन की आवश्यकता

ऐश्वर्या
तीन साल तक बिना किसी परेशानी के चलने के बाद, मैकबुक में कुछ समस्याएँ आने लगीं। वह एक Apple सर्विस सेंटर गई, जहाँ समस्या का निदान करने के लिए उनसे 2,600 रुपये लिए गए। मरम्मत के लिए और भी शुल्क लिया गया। उसी समय, Apple ने अपग्रेडेड फीचर्स और बेहतर कैमरे के साथ एक नया पचीवदम मॉडल पेश किया। Apple Inc के R-D ने इसे संभव बनाया। नए संस्करण के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग रणनीति ने लोगों के बीच काफी क्रेज पैदा किया है। पहला मामला सर्विसिटाइजेशन का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जबकि दूसरा सर्विसिफिकेशन का उदाहरण प्रस्तुत करता है — एक बहुत व्यापक सर्विटाइजेशन एक उत्पाद—कॅंट्रिट कंपनी में सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया है, ताकि अतिरिक्त राजस्व धाराएँ उत्पन्न की जा सकें और ग्राहकों को लगातार वांछित परिणाम दिए जाएं। अक्सर इस हद तक कि कंपनी का मुख्य रूप से समाधान—कॅंट्रिट हो जाती है। इसका क्लासिक उदाहरण ग्राहक सेवा सेवाएँ, नेटपिलक्स और स्पॉटिफाई हैं। 1980 के दशक में, निर्माताओं के लिए खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग करने और क्लाइंट कनेक्शन विकसित करने के साधन के रूप में सर्विसिटाइजेशन की अवधारणा लोकप्रिय हो गई। दूसरी ओर, औद्योगिक उत्पादन को डिजाइन, R-D, प्रोटोटाइपिंग सेवाएँ, परिवहन, विपणन, ब्रांडिंग, IT सेवाएँ (उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन में इनविल्टर ऐप्स) विविध सेवाएँ जैसे

कला के रूप में ओलिपिक

आदित्य

जब बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने ली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का कल्पना की थी, तो उनके मन में एक ऐसा मॉडल था जो स्पष्ट रूप से प्राचीन ग्रीस से प्रेरित था, केवल इचर्ड वैगनर द्वारा बकालत के गई "कला के संपूर्ण कार्य" से प्रेरित था। खेल एक साधारण न प्रतियोगिता नहीं थे, बल्कि अकलात्मक आयोजन था जिसमें लीटों की हरकतों को कला के विभिन्न रूपों – जैसे संगीत के साथ-साथ डांगा जाता था। संगीत वास्तव में लिपिक में प्रमुखता से शामिल है। जर्मन संगीतकार, रिचर्ड वैगनर ने 1936 के बर्लिन खेलों में वर्णन किया, जबकि परेडी मर्करीन लेकर वैगेलिस, फिलिप ग्लास लेकर जॉन विलियम्स तक, सभी नाकार विभिन्न ओलंपिक खेलों में संगीत रचना या प्रदर्शन में शामिल हैं। कुबर्टिन की दृष्टि में कला-प्रतियोगिताएँ भी शामिल थीं। 1912 के स्टॉकहोम खेलों में वास्तुकला, हित्य, संगीत, चित्रकला और

मूर्तिकला तलवारबाजी या रस्साकशी के साथ—साथ शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि कुबर्टिन ने साहित्य के लिए स्वर्ण पदक जीता, उन्होंने छद्म नाम से जर्मन में लिखे गए “ओड टू स्पोर्ट” के साथ प्रतियोगिता में प्रवेश किया था। इसके बाद, प्रत्येक ओलंपिक खेलों में ऐसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, कभी—कभी संग्रहालयों के साथ साझेदारी में— 1932 के ओलंपिक खेलों में लॉस एंजिल्स संग्रहालय में एक प्रदर्शनी शामिल थी जो जनता के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुई। हालाँकि, युद्ध के बाद ये प्रतियोगिताएँ मुश्किल से बची रहीं और 1952 में उन्हें छोड़ दिया गया। उनके स्थान पर, ओलंपिक चार्टर के पहले अनुच्छेद की भावना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित किया गयारू घ्येल को संस्कृति और शिक्षा के साथ मिलाकर, ओलंपिकवाद प्रयास के आनंद, अच्छे उदाहरण के शैक्षिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वभौमिक मौलिक

नैतिक सिद्धांतों के सम्मान के आधार पर जीवन जीने का एक तरीका बनाना चाहता है। ऐसे आयोजन, जिन्हें कभी-कभी शास्त्रीय ओलंपियाडश के रूप में संदर्भित किया जाता है, खेल और कला के बीच के रिश्ते को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। इस महीने पेरिस खेलों की ओर बढ़ते हुए, कला प्रदर्शनियों ने पेरिस — और वास्तव में फ्रांस — पर कब्जा कर लिया है, जिससे संस्थान खेलों के विज्ञापनदाताओं में बदल गए हैं। लौवर संग्रहालय आधुनिक खेलों के शास्त्रीय स्रोतों को ट्रैक करता है। कलाउड मोनेट की कुछ बेहतरीन पैटिंग रखने वाले संग्रहालय मार्मटन मोनेट ने 1870 से 1930 के बीच कलाकारों और खेलों के बारे में एक प्रदर्शनी लगाई है। इसके प्रदर्शन में गुस्ताव कैलेबोटे, जॉर्ज बेलोज और अन्य जैसे चित्रकारों द्वारा घुड़सवारी, मुक्केबाजी, तैराकी या नौकायन की पैटिंग शामिल हैं। आप्रवासन के इतिहास का संग्रहालय इस आयोजन के लिए अधिक राजनीतिक दृष्टिकोण



सड़कें न हो जरूरतमंदों का घर

विनाद
हमारे

हमार शहरा क हर कान में
जहाँ पर जीवन एक अलग लय में
ता है और जहाँ सपनों को उड़ने
लिए पंख मिलते हैं, इसके पीछे
कड़वी हकीकत छिपी है, जिसे
उसर नजरअंदाज कर दिया जाता
शहरी जरूरतमंद, जो शहर को
वित रखने के लिए कड़ी मेहनत
ते हैं, उन्हें जीवन की बुनियादी
लरतों के बिना, खुद को ही
गालना पड़ता है। गर्म भोजन, साफ
बड़े और सोने के लिए सुरक्षित
गह उनके लिए सिर्फ एक दूर का
ना होता है। सोचिए, यदि आपका
सड़क के किनारे हो और पूरी
ह से अस्थायी हो, जो मौसम की
झेलने के लिए सबसे आगे खड़ा
और सड़क के किनारे होने की
गह से हर पल अपने ऊपर खतरा
लिए हो, तो यह कैसा लगेगा?

आर अपन पारवार क साथ सुकून से रह सके। फिर भी, ये सपने कई लोगों को हासिल नहीं हो पाते, और ये लोग गरीबी के लगातार संघर्ष के साए में ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। यह कितना हृदयविदारक है कि किसी की एक पल की जरा—सी लापरवाही कैसे किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। एक तेजी से चलती कार, एक ध्यान भटका डुआँड्राइवर, और एक पल में एक जीवन समाप्त हो जाता है। निर्दोष पीड़ित, जिसकी केवल इतनी गलती थी कि उसने एक रात बिताने के लिए सड़क के किनारे का सहारा लिया था, एक्सीडेंट की वजह से मरने वालों की संख्या में महज एक दुखद आँकड़ा बन कर रह जाता है। हाल ही में वित वर्ष 2024 के लिए बजट पेश किया गया, जिसमें हाशिए पर खड़े लोगों के लिए एक उम्मीद की

करण उभरा ह। सरकार न अगल पाँच सालों में एक करोड़ शहरी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता की घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत आएगी। यह पहल सिर्फ़ एक नीति नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक वरदान भी है, जो प्रगति की दौड़ में सबसे पीछे रह गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा में एक व्याज सब्सिडी भी शामिल है, जो सरती दरों पर लोन देने का वादा करती है, जिससे कई लोगों का अपने घर का मालिक बनने का सपना सच हो सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घरों की योजना के साथ, सरकार हर नागरिक को एक सुरक्षित जगह देने की दिशा में

एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह पहल हमारे देश के कमजोर और जरुरतमंद लोगों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। यह उनकी संघर्षों की मान्यता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य देने की प्रतिबद्धता है। सिर पर छत की परिभाषा केवल आश्रय मात्र ही नहीं होती है, बल्कि यह गरिमा, सुरक्षा और उम्मीद का प्रतीक भी होती है। यह लोगों को बिना लगातार विस्थापन के डर के, एक बेहतर जीवन बनाने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। अगले पाँच वर्षों की ओर गौर करेंगे, तो हम पाएँगे और यह सच भी है कि हर ऑकड़े के पीछे एक इंसान होता है, जिसे सपने, आकांक्षाएँ और गरिमा के साथ जीवन जीने का हक है। आइए, हम भी सरकार के साथ मिलकर उन सभी पहलों का समर्थन करें, जो शहरों में रहने वाले गरिमा का बहतर जीवन देने का प्रयास करती हैं और सुनिश्चित करें कि वे शहर की सड़कों पर अपना जीवन जीने के लिए मजबूर न हों। साथ मिलकर, हम एक ऐसे समाज की स्थापना कर सकते हैं, जहाँ हर किसी को एक बेहतर जीवन का उचित मौका मिले, और जहाँ सड़कें प्रगति के रास्ते होंगे गरीबी की जेल नहीं। एक घर सिर्फ चार दीवारें और एक छत से ज्यादा होता है। यह एक आश्रय, आराम का स्थान और उम्मीद का प्रतीक होता है। आइए, इस सपने को हर नागरिक और विशेष रूप से हर एक जरुरतमंद के लिए वास्तविकता बनाने की कोशिश करें, और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी और हमारे देश की प्रगति और समृद्धि की यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

सरकार के लिए चुनाती पश करेग कुछ विराधाभास

बीते

राजग सरकार का यह पहला बजट है। यह बजट कई मायनों में खास है, जो अगले पांच वर्षों के लिए भवित्वान आर्थिक प्रबंधन के लिए तीतेगत ढांचे का प्रतिबिंब है। बजट शुरुआत दो सावधानियों के साथ ही है—बढ़ती वैश्विक आर्थिक निश्चितता और वैश्विक मुद्रासम्पति बढ़ता जोखिम। बजट भाषण में भवित्वान मंत्री द्वारा इन दो वैश्विक जोखिमों का उल्लेख दर्शाता है कि वर्त जैसी उभरती अर्थव्यवस्था इन वैश्विक जोखिमों के प्रति कितनी दंदनशील है। वित्त मंत्री ने जोर से कहा कि इन जोखिमों के अन्तर्गत भारत के विकास की गति रहेगी। लेकिन इसके लिए एक विश्वापक आर्थिक व्यवस्था, काऊ ऋण और घरेलू निवेश विभक्ता मांग में बढ़ोतरी बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में

अवसर पैदा करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में नौ प्राथमिकताएं बताई हैं। इनमें उत्पादकता, नौकरियां, सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार और सुधार शामिल हैं। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

हाल के वर्षों में बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस बार बजट में रोजगार, कौशल विकास, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम आकार के उद्यम (एमएसएमई) एवं मध्यवर्ग पर खास ध्यान दिया गया है। बजट में रोजगार बढ़ाने या निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित जिन

और डिजाइन उद्योग की जरूरतों के अनुरूप है। 60 हजार करोड़ रुपये में से, राज्य सरकारें 20 हजार करोड़ रुपये और उद्योग जगत 10 हजार करोड़ रुपये का योगदान देगा, जिसमें उसके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड भी शामिल हैं। इस बजट में अगली पीढ़ी के सुधारों से संबंधित कई घोषणाएं की गई हैं। ये सुधार भूमि, श्रम, पूंजी, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित हैं। बजट में जलवायु अनुकूलन और शमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने की खातिर सक्षम ढांचा बनाने पर भी जोर दिया गया है। इनमें से अधिकांश सुधारों का क्रियान्वयन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। खास तौर से भूमि से संबंधित कोई भी सुधार राज्य सरकारों को ही करना होगा। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, भूमि पर अधिकार,

सहित भूमि का स्वामित्व, और किराये का संग्रहय कृषि भूमि का हस्तांतरण तथा भूमि सुधार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। पिछले दो दशकों में भूमि एवं भूमि बाजार में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कुछ राज्यों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण एक बड़ी कामयाबी है। इस संबंध में राज्य स्तर पर व्यावहारिक भूमि संबंधी नीतिगत सुधारों के लिए विभिन्न राज्य स्तरीय नीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। इस मामले में केंद्र सरकार केवल राज्यों को सक्षम बना सकती है। ये सुधार केंद्र सरकार द्वारा संचालित नहीं किए जा सकते। इसलिए ऐसे सुधारों के कार्यान्वयन की सफलता के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत करनी होगी। इस बजट में आयकर ढांचे में इस तरह परिवर्तन किया गया है कि आयकर भुगतान के बाद लोगों

इसके लिए मूल छूट सीमा को बढ़ाया गया है, जिसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह पेंशनभोगीयों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती में छूट सीमा भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की गई है। चूंकि आधुनिक कर प्रणाली सरल और प्रशासन में आसान है, इसलिए आयकर अधिनियम की समीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। आयकर स्लैब में भी बदलाव किया गया है, जिससे आय वितरण के निचले छोर पर रहने वाले लोगों को मदद मिलेगी। हालांकि आयकर व्यवस्था वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के हाथों में कर चुकाने के बाद अधिक आय प्रदान करती प्रतीत होती है।

कर सकता है य परिणामस्वरूप, विनिर्माण संगठन उत्पादकता बढ़ाने के लिए सेवाओं पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं। दूसरा, परिवहन और संचार जैसी सेवाएँ विनिर्माण के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, जिससे विनिर्माण उद्यमों द्वारा मूल्य श्रृंखलाओं में सेवाओं की भागीदारी आवश्यक हो गई है। तीसरा, सेवाओं का उपयोग निर्माताओं के लिए ग्राहक संबंध स्थापित करने का एक तरीका हो सकता है। अंत में, कानूनी सेवाओं का उपयोग निर्माताओं को विनियमों का अनुपालन करने में सहायता करके बाजार में प्रवेश प्रतिबंधों को दूर करने में मदद करने के लिए किया जाता है। भारत का प्रदर्शन भारत के सकल घेरेलू उत्पाद में सेवाओं की हिस्सेदारी 1950-51 में 29.5:

एक हो गई है। इसके अलावा, 1991 के सुधारों के बाद सेवाओं के निर्यात में तेजी आई और 2008 में वैशिक वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था को सहारा देने में इसने प्रमुख भूमिका निभाई। सेवाओं के निर्यात की संरचना परिवहन जैसे पारंपरिक उप-क्षेत्रों से बदलकर आईटी-बीपीओ की ओर हो गई है, जिसने सेवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया है। इसी समय, विनिर्माण निर्यात में सेवाओं का योगदान पिछले कुछ वर्षों में 2000 में 17: से बढ़कर 2018 में 23: हो गया है। जबकि OECD देशों में व्यावसायिक सेवाएँ विनिर्माण निर्यात में लगभग 30: योगदान देती हैं, भारत का हिस्सा 25: से भी कम रहा है। यह भारत को विनिर्माण के सेवाकरण में लाभ उठाने की एक

नए नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने संभाला कार्यभार

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में नए नगर आयुक्त सुधीर कुमार गहलोत ने गुरुवार को कार्यभार संभाला। इससे पहले वह इसी जिले में सीड़ीओ थे। नगर आयुक्त ने चार्ज संभालते ही अधिकारियों और महापौर के साथ बैठक की। साथ ही, नगर निगम और विकास कार्यों को समझा। शहर की स्थितियों से पहले से ही वाकिफ नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि शहर में राजस्व वसूली, सफाई और अतिक्रमण पर फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान जगह-जगह सड़कों पर खारब हो गई हैं। ऐसे में शहर की सड़कों का सर्व कराकर उन्हें गड़मुक्त कराया जाएगा। साथ ही, वाकिफ की समस्या को दूर करने के लिए कैप लगाया प्राथमिकता का आधार पर दूर किया जाएगा। हर दूरी का बदला 700 करोड़ तक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। वहीं शहर में घड़ल्ले से बन रहे फ्लैट्स के नामांतरण की प्रक्रिया दुरुस्त की जाएगी। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि बारिश का देखते हुए जलभाराव की समस्या का त्वरित निदान और एंटी लावा का छिड़काव व फॉर्मिंग का कार्य भी तेज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली तेज करने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सूरत जैसे छाटे शहर में राजस्व वसूली काफी बेहतर है। इसके अलावा कानपुर में जाम की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, जिसे चिन्हित करने के साथ ही अभियान चलाया जाएगा। सोसाइटी ब्लोकों में होने वाले जलभाराव का भी सर्व कर उसके निराकरण की बात नगर आयुक्त ने कही। चार्ज लेने के बाद उन्होंने महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की।

नगर निगम कानपुर

जाएगा। हाउस टेक्स में विलिंग की समस्याओं को प्राथमिकता का आधार पर दूर किया जाएगा। इसके अलावा पूरे शहर में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा। वहीं शहर में घड़ल्ले से बन रहे फ्लैट्स के नामांतरण की प्रक्रिया दुरुस्त की जाएगी। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि बारिश का देखते हुए जलभाराव की समस्या का त्वरित निदान और एंटी लावा का छिड़काव व फॉर्मिंग का कार्य भी तेज किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने राजस्व वसूली तेज करने और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सूरत जैसे छाटे शहर में राजस्व वसूली काफी बेहतर है। इसके अलावा कानपुर में जाम की सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण है, जिसे चिन्हित करने के साथ ही अभियान चलाया जाएगा। सोसाइटी ब्लोकों में होने वाले जलभाराव का भी सर्व कर उसके निराकरण की बात नगर आयुक्त ने कही। चार्ज लेने के बाद उन्होंने महापौर प्रमिला पांडेय से मुलाकात की।

महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल, सहयोगी पति को दो साल का कारावास

कानपुर, संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब पांच साल पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पति व उसके दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जजधफटीरी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसंदर्भ करते हुए पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस जहार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति ब्रजेश नेशेवाल है। 20 नवंबर 2019 की रात करीब दस बजे उसका पति क्षेत्र के अकेली निवासी अपने दोषी हरिकेश को धर लेकर आया और दोनों ने शराब पी। जब पति नशे में हो गया तब हरिकेश ने पुलिस को विरोध करने पर पति ने उसे चुप रहने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जजधफ टी सी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई अपर हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसंदर्भ करते हुए पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस जहार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास होगा। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति ब्रजेश नेशेवाल है। 20 नवंबर 2019 की रात करीब दस बजे उसका पति क्षेत्र के अकेली निवासी अपने दोषी हरिकेश को धर लेकर आया और दोनों ने शराब पी। जब पति नशे में हो गया तब हरिकेश ने पुलिस को विरोध करने पर पति ने उसे चुप रहने की धमकी दी। मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जजधफ टी सी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई अपर हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसंदर्भ करते हुए पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस जहार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो साल के कठोर कारावास काटना होगा। वहीं दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —

फोटो रु अमर उजला

इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर पति को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

मामले पर पहुंचे अधिकारी —